सरपंचों के हाथों में गांवों के विकास की बागडोर : भजनलाल शर्मा

बिना भेदभाव सभी विधानसभा क्षेत्रों के गांवों को दिया बजट : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गरीब, किसान और पशुपालकों को मजबूती देकर ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. भीमराव अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह के ग्रामोदय के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का फोकस गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने पर है।

- **फार्मर आईडी के लिए 5 फरवरी से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लगेंगे शिविर**

सरपंच संघ राजस्थान द्वारा आयोजित पंचायतीराज सशक्तीकरण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया।

शर्मा मंगलवार को सरपंच संघ राजस्थान द्वारा आयोजित पंचायतीराज सशक्तीकरण एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरपंचों के हाथों में गांवों के विकास की बागडोर होती है और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उद्धार में सरपंच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। शर्मा ने कहा कि यदि उनकी इच्छाशक्ति मजबूत हो, दूरदृष्टि हो और लोगों का साथ हो तो गांवों का कायाकल्प किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि के रूप में सरपंचों के पास लोगो की सेवा का अवसर होता है और इसी सेवाभाव के साथ राजस्थान के प्रतिभाशाली और समर्पित सरपंच अपने गांवों को विकास की राह पर ले जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सरपंच के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि आप लोगों को देखकर मेरा हृदय आज उसी भाव से भर उठा है, जब मैं स्वंय सरपंच था। उन्होंने कहा कि मैं गांव की मिट्टी में ही पला-बढ़ा हूं और उसी मिट्टी की सोंधी खुशबू और चुनौतियों के बीच जिया हूं।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतीराज के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। हमने राज्य बजट में बिना भेदभाव राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के गांवों के लिए बजट का प्रावधान किया। पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 1 अप्रेल, 2024 से 10 प्रतिशत वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 371 ग्राम पंचायत भवनों का कार्य पूर्ण करवाया गया है। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 200 विधान सभा क्षेत्रों में 1 हजार करोड़ रुपये की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कों के 1 हजार 631 कार्य प्रारंभ किए जाकर 530 किलोमीटर लम्बाई के 309 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में किसानों और पशुपालकों के लिए प्राथमिकता के साथ योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए पीएम-कुसुम योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। किसान अपनी अनुपजाऊ भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर ऊर्जा उत्पादक भी बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हजार रुपये के अतिरिक्त अनुदान का लाभ भी किसानों को दे रही है। अब तक हम 1355 करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को जमाबंदी, खसरा गिरदावरी और राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा नामांतरण की प्रक्रिया को पेपरलेस किया गया है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है। इसके तहत 24 हजार से अधिक गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है। पशुपालकों को निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन कॉल सेंटर सेवा 1962 शुरू की गई है। 536 मोबाइल वाहनों द्वारा 30 लाख पशुओं का उपचार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने का काम भी हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कर रही है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में 72 हजार से अधिक कूपन जारी कर गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजीविका परियोजना के तहत 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के अपने घर का सपना साकार हो रहा है।

शिक्षामंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक

जयपुर। शिक्षामंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन व राज्य में शिक्षा के संरचनात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जाने वाले मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के बिंदूओं सहित शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धित एवं आवश्यक सुधार के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा के सुढढीकरण एवं मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अब तक 12 जिलों का स्थानीय शब्दकोश तैयार किया जा चुका है। अन्य जिलों का शब्दकोश भी जल्द तैयार कर लिया जाएगा।

उन्होंने आरएससीईआरटी में योग्य शिक्षाविदों की सहायता लेकर गुणवत्तापूर्ण कार्य व विद्यार्थी हितों से जुडे कार्यों को चरणबद्ध रूप से संपादित करने की प्रतिबद्धता दिखाई। साथ ही शिक्षाविदों द्वारा साझा किए सुझावों पर विचार विमर्श करने और अमल में लाने का आश्वासन भी दिया। इससे पहले शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य एनईपी में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाना, राजकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। अभियान के तहत एनईपी 2020 के 202 टास्क में से 185 टास्क शामिल होंगे, जिन्हें चार बिंदूओं में संपादित किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने देखी जयपुर फुट की निर्माण विधि

मुख्य सचिव सुधांश पन्त ने मंगलवार को भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) का निरीक्षण किया और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माण विधि देखी।

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव सुधांश पन्त ने मंगलवार को भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) का निरीक्षण किया और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माण विधि देखी। पन्त ने करीब दो घण्टे तक जयपुर फुट निर्माण से जुड़े कार्यो के बारे में जानकारी ली और और विभिन्न प्रान्तों से आए हुए दिव्यांगों से बातचीत की।

बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता, सचिव भूपेन्द्र मेहता और सचिव (तकनीकी) डॉ. दीपेन्द्र मेहता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एस. बिस्सा ने मुख्य सचिव सुधांश पन्त का स्वागत किया। डी.आर. मेहता ने पन्त को बताया कि अब तक देश-विदेशों के 22 लाख से अधिक दिव्यांगों को जयपुर फुट लगाकर लाभांवित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जयपुर फुट के पदचिन्ह 40 देशों में देखे जा सकते हैं, जहां 40 हजार से अधिक दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया है। पन्त ने बी.एम.वी.एस.एस. द्वारा संचालित फिजियोथैरेपी केन्द्र और उत्तर भारत के सबसे बड़े लकवाग्रस्त मरीजों को पुर्नवास के लिए हाल ही में स्थापित गणपत सरोज सिंघवी रोबोटिक रिहेबिलिटेशन केन्द्र का भी निरीक्षण किया।

घनश्याम तिवाड़ी ने राज्यसभा में उठाया भांकरोटा सड़क दुर्घटना का मामला

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने मंगलवार को सदन में दिल्ली-अजमेर बायपास पर गैस से भरे ट्रक और बस की दुर्घटना के बाद हुए भीषण हादसे के मामले को उठाया। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर के ब्लास्ट के कारण काफ़ी संख्या में जान माल की हानि हुई। इस घटना में कई निर्दोषों की जान गयी। इस हादसे में 4 लोग तो मौके पर ही जिंदा जल गए थे। 8 लोगों ने उसी दिन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। हादसा इतना भीषण था कि 5 शवों की पहचान डीएनए सैंपल से की गई।

घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि एलपीजी टैंकर के नोजल फटने से गैस करीब 500 मीटर एरिया तक फैल गई। गाड़ियारें में स्पार्क और अलग-अलग कारणों से वहां मौजूद 40 से ज्यादा गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई थी। टैंकर के ठीक पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई थी। गैस टैंकर के फटने से न केवल मानव जीवन पर संकट आया, बल्कि आसपास के इलाके में स्थित संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ।

राज्यसभा सांसद तिवाड़ी ने पूरे सदन का ध्यान विषय पर दिलाते कहा कि इस प्रकार की घटना से ना केवल सामाजिक स्थिति पर अपितु सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का मुख्यत: कारण होता है ट्रैफ़िक को सुचारु रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जाना। जिस स्थान पर यह घटना हुई वहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूसरी तरफ़ जाने के लिए यू टर्न था वहां गैस टैंकर के यू-टर्न के दौरान दूसरे अनियंत्रित वाहन के कारण हादसा हुआ। तिवाड़ी ने समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे स्थानों का चयन करते हुए इन यू टर्न को बंद कराए तथा वैकल्पिक रास्तों का निर्माण हो ताकि ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। साथ ही ऐसे पदार्थ जो ज्वलनशील एवं अति - ज्वलनशील की श्रेणी में आते हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उचित प्रबंधन तथा संभावित खतरों और उनकी रोकथाम के बारे में इससे जुड़े कर्मचारियों/व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाए।

समरावता उपद्रव प्रकरण में 11 को पेश होगा आरोप पत्र

जयपुर, 4 फरवरी। देवली-उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के एसडीएम से मारपीट के बाद समरावता में हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने मंगलवार को हाईकोर्ट में कहा कि उन्होंने अनुसंधान पूरा कर लिया है। वहीं इस मामले में 11 फरवरी को संबंधित कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाएगा। राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश नरेश मीणा की याचिका पर दिया।

गत सुनवाई पर अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से अदालत को घटना का वीडियो दिखाया था। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि घटना का जिम्मेदार नरेश मीणा है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि वह घटना के समय पुलिस अभिरक्षा में था। ऐसे में वह भीड को उपद्रव के लिए कैसे भडका सकता है। इस मामले में 18 आरोपियों की टोंक के सेशन कोर्ट से और करीब 40 आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत हो चुकी है। गौरतलब है कि देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उप चुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम से मारपीट की थी। इसके बाद उसके समर्थकों ने उपद्रव फैलाया था। घटना को लेकर पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

108 साधकों ने किया "सूर्य नमस्कार"

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि "सूर्य नमस्कार" भारतीय संस्कृति से जुड़ी महान योग परम्परा है। यह स्वास्थ्य के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार मन व शरीर दोनों को तंदुरुस्त रखता है। बागडे मंगलवार को क्रीडा भारती संगठन द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में सूर्य सप्तमी पर आयोजित सामूहिक "सूर्य नमस्कार" कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 108 साधकों ने एक साथ "सूर्य नमस्कार" से जुड़ी योग क्रियाएं की।राज्यपाल ने कहा कि योग की भारतीय परंपरा सूर्य नमस्कार से ही प्रारंभ होती है।

- **'भारतीय संस्कृति से जुड़ी महान योग परम्परा "सूर्य नमस्कार" स्वास्थ्य के लिए वरदान'**

राज्यपाल ने सूर्य सप्तमी पर आयोजित "सूर्य नमस्कार" कार्यक्रम को संबोधित किया।

यह योग के आगे के आसनों के लिए हमें तैयार करता है। उन्होंने कहा कि "सूर्य नमस्कार" मनुष्य के भीतर की ऊर्जा का संधान कर तन और मन को स्वस्थ करता है। राज्यपाल ने प्रतिदिन हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते समय देने और "सूर्य नमस्कार" करने का आव्हान किया। उन्होंने क्रीड़ा भारती को देश की महत्वपूर्ण संगठन बताते हुए कहा कि पारंपरिक खेलों के साथ भारतीय संस्कृति से जुडी इसकी गतिविधियां अनुकरणीय है।इस अवसर पर राज्यपाल बागडे ने क्रीडा भारती की स्मारिका "खेल सृष्टि" का भी लोकार्पण किया।

'राजस्थान में रेल अवसंरचना के लिए 9960 करोड़ रु. बजट आवंटित कराया'

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025-26 में 9960 करोड़ रूपए आवंटित करने पर आभार व्यक्त किया। राठौड़ ने कहा कि रेल बजट में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और इन्फ्रास्ट्रेक्चर के विस्तार के साथ आधुनिकीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। इससे यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकार प्रदेश की यातायात व्यवस्था को सुदृढीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में रेल बजट में राजस्थान को आवंटित राशि से इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। 2009 से 2014 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तुलना में राजस्थान को

- **सांसद मदन राठौड़ ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया**

14.5 गुणा बजट आवंटित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास की नीति के आधार पर रेलवे में कार्य किया जा रहा है। रेलवे के इन्फ्रास्ट्रेक्चर को मजबूत करने की दिशा में रेल मंत्री ने विशेष फोकस किया है। राजस्थान के 85 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तहत विकसित किया जा रहा है। जबकि सुरक्षा के लिहाज से 10 हजार लोको मोटिव्स में कवच सिस्टम लगाया जा रहा है।

कार्यकाल पूरा होने के बाद 6759 सरपंचों को प्रशासक किस प्रावधान में लगाया ?

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने के मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में बताने को कहा है कि पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम क्या है और वे कब चुनाव कराएंगे। अदालत ने यह भी पूछा है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनमें सरपंचों को प्रशासक लगाने के क्या प्रावधान हैं। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश गिर्राज सिंह व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशासक केवल अस्थाई व्यवस्था और कम समय के लिए ही लगाए जा सकते हैं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा व अजय पूनिया ने कहा कि राज्य के

- **राजस्थान हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा**
- **अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि, प्रदेश में पंचायतों के चुनाव कब कराए जाएंगे और उसका कार्यक्रम क्या है?**

ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग ने 16 जनवरी 2025 की नोटिफिकेशन के जारी कर संविधान व पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पंचायतों को भंग किए बिना ही निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगा दिया है। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 243 ई व 243 के और राजस्थान पंचायत राज एक्ट की धारा 17 व 94 की अवहेलना है। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद आम चुनाव नहीं कराना गलत है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में ना तो चुनाव कराए जाने की कोई सीमा तय है और ना प्रशासकों के कार्यकाल की ही कोई तिथि तय की है। जबकि संवैधानिक प्रावधानों में ना तो पंचायतों का कार्यकाल बढाया जा सकता है और ना ही उनमें प्रशासक लगाए जा सकते हैं। वहीं महाधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने पंचायत राज एक्ट की धारा 95 के तहत ही सरपंचों को प्रशासक लगाया है। इसके साथ ही महाधिवक्ता ने विस्तृत जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय देते हुए इस संबंध में जानकारी देने को कहा है।

दुकान में दो बार चोरी की वारदात

जयपुर। आदर्श नगर थाना इलाके में एक दुकान में चोर ने तीन दिन में दो बार चोरी की वारदात कर डाली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार सिंधी कॉलोनी निवासी शंकर लाल ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी दुकान बर्फखाना के पास है। 20 जनवरी की शाम करीब साढ़े चार बजे एक युवक आया और उसकी दुकान में घुसकर गल्ला तोड़कर 25 से 30 हजार रुपए ले गया। यह पूरी घटना दुकान के बाहर व अंदर लगे सीसीटीवी कैमरें में कैद हो गई। 23 जनवरी की रात करीब पौने बारह बजे चोर एक बार फिर दुकान का गेट तोड़कर अंदर घुसा और दुकान से 20 हजार रुपए और एलईडी टीवी सहित अन्य सामान ले गया। लगातार हो रही घटना से परेशान होकर पीडितथाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है।

जलग्रहण यात्रा का शुभारम्भ 5 फरवरी से

जयपुर। केंद्र सरकार द्वारा जलग्रहण विकास के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम बारां जिले की पंचायत समिति, किशनगंज की ग्राम पंचायत किशनगंज में 5 फरवरी को प्रात: 11 बजे से प्रारम्भ होगा। मो. जुनैद पीपी, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण ने बताया किजलग्रहण यात्रा के आयोजन का उद्देश्य जलग्रहण गतिविधियों की जानकारी जन-जन को देना, इससे होने वाले लाभों के बारे में अवगत कराना तथा परियोजना से जुडाव सुनिश्चित करना है। यह यात्रा राज्य में दो रथों द्वारा पृथक-पृथक मार्गों से 27 जिलों की 107 परियोजना अन्तर्गत 214 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

निदेशक ने बताया कि इस कार्यक्रम में स्थानीय जन प्रतिनिधिगण भाग लेंगे एवं केन्द्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का कार्यक्रम लाईव प्रसारित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शुभारम्भ समारोह में अनेकानेक गतिविधियां सम्पादित की जावेगी, जिनमें नवीन कार्य का भूमि पूजन, श्रमदान, वानिकी एवं उद्यानिकी पौधों का वृक्षारोपण, पूर्ण कार्यों का लोकार्पण, जलग्रहण गीत, जल शपथ, कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिये विभूतियों का सम्मान, प्रदर्शनी, जलग्रहण गैलेरी इत्यादि सम्मिलित है।

उन्होंने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से मार्च 2026 तक के लिये राज्य में कुल 149 परियोजनाएं 7.50 लाख हैक्टेयर हेतु स्वीकृत की गई है, जिनकी लागत 1858.55 करोड़ रुपये है। मो. जुनेद ने बताया कि इस परियोजना में प्रदेश की कुल 30 जिलों की 148 पंचायत समितियों की 785 ग्राम पंचायतों की 985 गांवों को शामिल किया गया है। परियोजना अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य का अंशदान 60:40 है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्राकृतिक संस्थानों जैसे जल, जंगल, जमीन, जानवर एवं जन का समन्वित रूप से संरक्षण और विकास एक आवश्यक घटक है।

जयपुर जिले में आज होगा किसान रजिस्ट्री शिविरों का आगाज

हर किसान को मिलेगी 11 अंकों की एक विशिष्ट पहचान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में 5 फरवरी से जयपुर जिले की ग्राम पंचायतों में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन होगा। शिविरों के सफल आयोजन के लिए कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर जिला स्तरीय हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। अपनी ग्राम पंचायत में शिविर के आयोजन सहित अन्य जानकारियां हासिल करने के लिए आमजन एवं किसान दूरभाष नंबर 0141-2209905, 0141-2209906 पर संपर्क कर सकते हैं।

बुधवार 5 फरवरी को जयपुर जिले के मौजमाबाद के मोखमपुरा, किशनगढ़-रेनवाल के लुनियावास, जयपुर के सुमेल, जोबनेर के ढाणी नागान, आमेर के लबाना, सांगानेर के गोनेर, फुलेरा-सांभरलेक के हबसपुरा, जमवारामगढ़ के भानपुरा कलां, बस्सी के कानोता, कालवाड़ के बेगस, चौमूं के नांगल कलां, शाहपुरा के नायन, तुंगा के माधोगढ़, माधोराजपुरा के ढाबिच, फागी के लदाना, चाकसू के टुटोली, दूदू के सुनाड़िया सहित कोटखावदा और आंधी ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन होगा।

कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जयपुर जिले में किसान रजिस्ट्री शिविरों के सफल आयोजन एवं जिले के समस्त किसानों का एग्रीस्टैक पर रजिस्ट्रेशन

- **31 मार्च तक जयपुर की ग्राम पंचायतों में लगाए जाएंगे शिविर**

सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने शिविरों के व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिये हैं ताकि जिले के प्रत्येक किसान को ना केवल शिविरों के आयोजन की जानकारी हो बल्कि शिविरों में किसान फार्मर आईडी बनाने के साथ-साथ अन्य विभागीय योजनाओं से लाभांवित हों सकें। एग्रीस्टैक योजनांतर्गत जयपुर में किसान रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च तक किया जायेगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में किसानों की विशिष्ट किसान आईडी बनाई जायेगी। शिविरों का आयोजन प्रात: 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक किया जाएगा।

शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार सहित पशुपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभांवित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जायेगी। किसानों द्वारा आईडी बनवाने के लिये आधार कार्ड, जमाबंदी, मोबाईल नम्बर की जरूरत होगी।

भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक आसान पहुंच करने, प्रधानमंत्री किसान/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त आईडी उपयोगी होगी।

सौभाग्य योजना से 2.86 करोड़ घर रोशन किए : मदन राठौड़

जयपुर। केन्द्र सरकार की ओर से हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए शुरू की गई "सौभाग्य योजना" के तहत अब तक 2.86 करोड घरों को बिजली से रोशन किया गया है। इसके साथ ही दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से देशभर में 18 हजार 374 गांवो तक बिजली पहुंचाई गई है। यह जानकारी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से राज्यसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न के जवाब में दी गई है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही हर घर को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है। इसके चलते वर्ष 2024 में देशभर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में औसतन बिजली सप्लाई भी 21.9 से 23.4 घंटे रही है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए

- **वर्ष 2024 में देशभर में औसतन 21 से 23 घंटे हुई बिजली आपूर्ति : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष**

कहा है कि 2014 जब उन्होंने पीएम की कुर्सी संभाली थी तो देश में कुल बिजली उत्पादन 230 गीगावाट था जो अब बढकर 462 गीगावाट हो गया है। जिससे देश बिजली की कमी से मुक्त होकर पर्याप्त उपलब्धता की ओर अग्रसर हो रहा है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड ने कहा कि केन्द्र सरकार के दूरगामी निर्णयों के चलते आने वाले वर्षो में भारत बिजली उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान पर होगा। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। वर्ष 2032 तक देश में तापीय बिजली के उत्पादन में 80 हजार मेगावाट की बढोतरी हो जाएगी। जिसके तहत वर्ष 2023-24 में 19 हजार 200 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए अनुबंध दे दिए गए है। वहीं जलविद्युत उत्पादन में वर्ष 2032 तक 50 हजार 760 मेगावाट की बढोतरी होगी। इसके अलावा नवीकरणीय उर्जा के उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है जो भविष्य के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड ने कहा कि बिजली उत्पादन के साथ ही ग्रिड से राज्य और गांवो में दूर दराज तक बिजली लाइनें डालने के कार्य में भी तेजी आई है। ऐसे में राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार वर्ष 2032 तक एक लाख 91 हजार 474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के इन प्रयासों से देश और राज्य उर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है।